श्री शिव नारायण: मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न सरकार के विचाराधीन है क्या उस में यह मांग भी है कि दिल्ली में असेम्बली बना दी जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, हां, वह मांग तो है ही ।

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether the different political parties who are asking for a reconsideration have been able, by and large, to come to any agreement among themselves for the future set-up of Delhi?

Shri Nanda: I have discussed with them the proposals relating to, as I said, the reconstitution of the Corporation. That was what I was called upon to do. Regarding that, there were certain differences.

श्री क० ना० तिवारी : दिल्ली की जो मांग है, उस में क्या वह लोग यू० पी०, पंजाब और दूसरे जो नजदीक के प्रदेश हैं उन का हिस्सा मिलाना चाहते हैं । यदि हां, तो उन सरकारों से बातचीत क्यों नहीं हो रही है ?

श्री नन्दा : उस में किसी माननीय सदस्य की स्टेट का हिस्सा लेने का कोई सवाल नहीं है ।

Shri S. M. Banerjee: May I know when a final decision is likely to be taken and what is their specific objection to giving a State Legislature to Delhi?

Mr. Speaker: It has been already answered.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के सम्बन्ध में सरकार के इतने देर करने से जो एक सन्दिग्ध स्थिति प्रशासन में और दिल्ली के नागरिकों में उत्पन्न हो रही है उस को समाप्त करने की दिशा में सरकार कब तक अन्तिम निर्णय ले सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पूछा गया है और दो दफे इस के बारे में कहा गया है ।

Use of Hindi for Official Purposes

\+

*54. **Shri Jagdev Singh Siddhanti:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri D. C. Sharma:
Shri Vidya Charan Shukla:
Shri Vishram Prasad:
Shri Bagri:
Shri Yashpal Singh:
Shri P. K. Deo:
Shri Solanki:
Shri Gulshan:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Mohan Swarup:
Shri Sarjoo Pandey:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 214 on the 16th September, 1964 regarding the appointment of the Hindi Salahkar Samiti to advise on matters relating to the propagation and development of Hindi and its progressive use for the official purposes of the Union and state:

(a) the brief outline of the suggestions and recommendations made by this Committee so far and the action taken or proposed to be taken thereon by Government; and

(b) the steps taken to make Hindi as the official language of the Union with effect from the 26th January, 1965 as envisaged in the Official Language Act, 1963

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3373 (i)/64].

(b) A comprehensive programme was taken in hand by Government in 1961 for facilitating the progressive use of Hindi. A note giving a brief account of the measures taken is laid

on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3373 (ii)/64]. Further steps are now being taken in pursuance of the recommendations made by the Hindi Salahkar Samiti.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सरकार यह बतलायेगी कि 26 जनवरी को कौन कौन से हिन्दी विषयक निर्णय हैं जो कि लागू कर दिये जायेंगे ।

श्री ल० ना० मिश्र : 26 जनवरी, 1965 से हिन्दी राज भाषा हो जायेगी और उस समय से वह राज भाषा कहलायेगी ?

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : जिन जिन मंत्रालयों में हिन्दी के विशेषज्ञ कर्मचारी नहीं हैं, उन के विषय में आपका क्या कार्य पूरा करने के लिये बाकी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि मैंने जो बयान सदन पटल पर रक्खे हैं उस में बाकी ब्योरा दिया है जो काम हुआ है उसका, और वह उस को देखें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहूंगा कि संघीय लोक सेवा आयोग में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाने का जो प्रश्न विचाराधीन था क्या उस पर कोई अन्तिम निर्णय हो गया है । यदि हां, तो उसका क्या व्यावहारिक रूप रहेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : सिद्धान्ततः तो वह है, केवल माडरेशन की बात है और उसके प्रबन्ध की बात है । जहां तक सिद्धान्त की बात है यह फैसला हो चुका है कि सन् 1965 के अक्तूबर से हिन्दी वैकल्पिक भाषा हो जायेगी ।

Shri D. C. Sharma: From the statement I find that Government was asked to take early steps to recognise the Pracharak Diploma of the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. May I know how long it will take the Government to do this innocuous and harmless thing and why the Government has taken so long in not having it implemented so far?

Shri L. N. Mishra: Some delay has been caused. We are in correspondence with the Education Ministry and we hope it will be finalised soon.

श्री अ० प्र० शर्मा : इस सदन में भूतपूर्व गृह मंत्री ने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसिज में, खास तौर से रेलवे की सबार्डिनेट सर्विसिज के लिये जो रिक्रूटमेंट होता है उस में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है वह अंग्रेजी में होता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके सम्बन्ध में फैसला हुआ है कि वह हिन्दी में लिया जायेगा । यदि हां, तो कब से ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे रेलवे कमीशन के बारे में ज्ञान नहीं है । लेकिन यह बात सही है कि नीचे की जो नौकरियां हैं उन में से कुछ की परीक्षा हिन्दी भाषा में ली जा रही है ।

श्री क० ना० तिवारी : स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने प्रज्ञा परीक्षा पास की है । मैं जानना चाहता हूं कि हर प्रान्त में कितने सरकारी अफसर इस परीक्षा में बैठे हैं और कितनों ने हर प्रान्त में इस परीक्षा को पास किया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह आंकड़ा तो इस समय मेरे पास नहीं है । लेकिन मेरा खयाल है कि जो हमने स्टेटमेंट 'बी' दिया है उसमें इसकी थोड़ी सी रूपरेखा रखी गई है कि कितने लोगों ने पास किया है और कितने लोगों ने हिन्दी सीखी है ।

श्री क० ना० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने हिन्दी सीखी है ?

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेंट नम्बर 1 को देखने से पता चलता है कि उसमें दिया गया है :

"The Home Minister may convene a meeting of the Chief Ministers of Hindi-speaking States to consider the measures that should be taken for facilitating the use of Hindi for all official purposes in the Hindi-speaking States.".

और इसका जवाब यह दिया गया है :

"The Home Minister has decided provisionally to convene a meeting of the Chief Ministers concerned some time in December 1964".

मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वाधीनता के 17 साल के बाद भी क्या गृह मंत्री जी को यह शक है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों ने हिन्दी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, उसको तरजीह नहीं दी है, उसको आगे नहीं बढ़ाया है ? सरकार का इस में क्या खयाल है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : बहुत कुछ हुआ है और मैं समझता हूं इससे और ज्यादा होने की गुंजाइश है ।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दी भाषी क्षेत्रों में मुख्य मंत्री हिन्दी को क्या कम करेंगे और क्या ज्यादा करेंगे । इसको ज्यादा और कम करने के क्या मानी हैं ?

श्री नन्दा : ज्यादा और कम करने का सवाल नहीं है । सरकार के लिए अपने कामों में उसका इस्तेमाल ज्यादा हो सके इस बारे में जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि अब तक आई० ए० एस० की परीक्षा में 70 प्रतिशत उम्मीदवार इसलिए फेल हो जाते हैं कि वे बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोल सकते ? अगर यह सच है तो यह कलंक देश के सिर से कब छूटेगा ?

Shri Kapur Singh: I want to know what steps, if any, the Government has taken to safeguard against erosion by Hindi into the official status of non-Hindi languages in bi-lingual States?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): This question would arise with regard to the examinations conducted by the Public Service Commission. Is that the question?

Shri Kapur Singh: No.

Shri Hathi: What else? Will he kindly repeat the question?

Shri Kapur Singh: I want to know what steps, if any, this Government has taken to safeguard against the erosion of by Hindi into the official status of non-Hindi languages in bi-lingual States such as in Punjab?

Shri Hathi: I do not think it is correct.

Mr. Speaker: He wanted to know what steps the Government have taken. "It is not correct" is no answer. He wanted to know what steps the Government have taken to safeguard the erosion of other languages by Hindi in the bi-lingual States such as Punjab.

Shri Hathi: So far as the regional languages are concerned they will be fully developed. There is no question of the regional languages being eroded by the use of Hindi.

Shri Nambiar: In view of the fact that the hon. Deputy Minister just now gave the answer that Hindi is going to be the Rashtrabhasha from 26th January, 1965, may I know—whether it is the Rashtrabhasha or the link language or whatever the status may be—whether Hindi is going to be imposed on the non-Hindi areas and what is the sort of thing that is going to be adopted in this regard (*Interruptions*)?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): If that question at all arises, my answer would be very clear and categorical. There is no question of

imposition. The policy has been explained, reiterated here time and again, and I think that stands. That policy and those declarations stand today, and I do not think the hon. Member needs any reassurance on that subject.

श्री काशी राम गुप्त : क्या यह सत्य है कि हिन्दी सलाहकार समिति के सुझावों में से बहुतों को मान्य नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा है कि वे सुझाव केवल सुझाव ही रहें और उनको अमल में न लाया जाए ?

श्री नन्दा : यह गलत बात है । अगर माननीय सदस्य स्टेटमेंट को देखें तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि बहुत सी रिकमन्डेशन्स मंजूर कर ली गयी हैं ।

Shri Hem Barua: May I know if the Home Ministry are aware of the fact that the hon. Education Minister has recently created some storm in the tea cup in Gujarat when he said that English will be taught from the fifth standard and, if so, what is the reaction of the Home Ministry to that? How do the Home Ministry want to quell the storm?

Shri Nanda: That does not arise out of this question.

Shri P. Venkatasubbaiah: The Education Minister has often said that English should be developed as a link language. If that is so, does it not come into conflict with the development of Hindi, resulting in the interests of the non-Hindi speaking people being jeopardised?

Shri Nanda: Both the objectives are being kept in view.

Rehabilitation Schemes

\+

*55. **Shri P. C. Borooah:**
Shri Bagri:
Shri Vishram Prasad:
Shri R. G. Dubey:
Shri Yashpal Singh:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri N. R. Laskar:
Smt. Jyotsna Chanda:

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned any schemes proposed by the Assam Government for the rehabilitation of new migrant families from East Pakistan;

(b) if so, the broad outlines and cost of the schemes; and

(c) the steps taken to implement those schemes?

The Deputy Minister in the Ministry of Rehabilitation (Dr. M. M. Das): (a) to (c). The Government of India have sanctioned nine schemes costing Rs. 84,94,740 for the rehabilitation of new migrants in Assam. A statement giving details of those schemes and the steps taken for their implementation is laid on the Table of the House. [*Placed in Library, See* No. LT-3374/64].

Shri P. C. Borooah: The hon. Deputy Minister has just now told us that about Rs. 84 lakhs has been given to the refugees numbering about 1,60,000 now in Assam, which comes to about Rs. 50 per head. How does this compare with the *per capita* rehabilitation grant sanctioned to the other States and how much more will be given to Assam State?

Dr. M. M. Das: There is some misapprehension in the mind of the hon. Member. The Assam Government has been sending to us a number of schemes for the rehabilitation of refugees. Out of those, up till now 9 schemes have been sanctioned costing about Rs. 84,94,000 and odd. 23 more schemes are under consideration and some more schemes are coming in.

Shri P. C. Borooah: May I know whether it is a fact that owing to the deteriorating economic condition of the refugees in Assam their camps are now being converted into trouble-spots and some refugees are already